Wasteland Development Task Force

3228. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Wasteland Development Task Force;

(b) if so, the details thereof indicating therein its membership and terms of reference;

(c) whether any time frame has been chalked out by the Task Force for development of those Wasteland areas which have been ignored since long; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT) (COL. RAO RAM SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The Department of Wastelands Development has taken a decision to create a Wastelands Development Task Force for developing the non-forest wastelands in the inaccessible and inhospitable areas of Bhind/ Morena districts in Madhya Pradesh State. The Force will be embodied under the Territorial Army Act and shall consist of ex-serviceman. The Force will be commanded by a core group from the Directorate of Territorial Army. The objectives of this Force would be to increase availability of biomass, specially fuelwood and fodder to the rural people. The Force would develop the non-forest wastelands allocated to it by the State Government through activities which would include soil and moisture conservation, afforestation, pasture development, horticulture and related activities.

(c) and (d) The State of Madhya Pradesh has been asked to earmark 1200 to 1500 ha of non-forest wastelands in the districts of Bhind/Morena. These wastelands are likely to be highly degraded, subject to a high degree of soil erosion and absence of vegetal cover. Hence no firm time-frame is possible for the development of such lands as this would depend on local conditions. However, the soil working and plantation of the lands allocated to the Wastelands Development Force in phase-I will be developed in a period ranging from 3 to 5 years.

ग्रामीण विकास पर किया गया व्यय

3229. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में राज्यवार कुल जनसंख्या कितनी है और प्रत्येक राज्य में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में, विशेषकर गुजरात राज्य में, ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत भाग खर्च किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के पश्चिमी भाग में ग्रामीण विकास पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) 1991 की जनगणना के आधार पर देश की राज्यवार कुल जनसंख्या के साथ-साथ प्रत्येक राज्य में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है (नीचे देखिए)।

(ख) प्रत्येक राज्य में और विशेष रूप से गुजरात में राष्ट्रीय आय का प्रतिशत, जिसे ग्रामीण विकास पर खर्च किया जा रहा है, को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) ग्रामीण गरीबों के रहन-सहन में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आबंटनों में वृद्धि करके निरन्तर प्रयास कर रही है। इसके परिणाम-स्वरूप समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम जैसे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत देश के पश्चिमी भाग अर्थात् गुजरात और महाराष्ट्र के कुल आवंटन (केन्द्र + राज्य) में वृद्धि का रुख रहा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

(लाख रू में)

राज्य	कुल आवंटन (केन्द्र + राज्य)	
	1992-93	1993-94
1. गुजरात	19636.93	26354.80
2. महाराष्ट्र	45776.64	66607.53

विवरण–I

पुरुष और महिला के अनुपात के साथ-साथ राज्यवार कुल जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार)

(1991 की जनगणना)

क्र० सं०	राज्य / संघशासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाख)	पुरुष प्रतिशत	महिला प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	665.08	50.7	49.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.65	53.8	46.2
3.	असम	224.14	52.0	48.0
4.	बिहार	863.74	52.3	47.7
5.	गोवा	11.70	50.8	49.2
6.	गुजरात	413.09	51.7	48.3
7.	हरियाणा	164.64	53.6	46.4
8.	हिमाचल प्रदेश	51.71	50.6	49.4
9.	जम्मू व कश्मीर	77.19	52.0	48.0
10.	कर्नाटक	449.77	51.0	49.0
11.	केरल	290.99	49.1	50.9
12.	मध्य प्रदेश	661.81	51 8	48.2
13.	महाराष्ट्र	789.37	51.7	48.3
14.	मणिपुर	18.37	51.1	48.9
15.	मेघालय	17.75	51.1	48.9
16.	मिजोरम	6.90	52.0	48.0
17.	नागालैंड	12.10	53.0	47.0
18.	उडीसा	316.60	50.7	49.3
19.	पंजाब	202.82	53.1	46.9
20.	राजस्थान	440.06	52.4	47.6
21.	सिक्किम	4.06	53.2	46.8
22.	तमिलनाडु	558.59	50.7	49.3
23.	त्रिपुरा	27.57	51.4	48.6
24.	उत्तर प्रदेश	1391.12	53.2	46.8
25.	पश्चिम बंगाल	680.78	52.2	47.8
26.	अण्डमान व निकोबार	2.81	55.0	45.0
27.	चण्डीगढ	6.42	55.8	44.2
28.	दादर व नगर हवेली	1.38	51.2	48.8
29.	दमन व दीव	1.02	50.8	49.2
30.	दिल्ली	94.21	54.7	45.3
31.	लक्षदीप	0.52	51.5	48.5
32.	पांडिचेरी	8.08	50.5	49.5
कुल अखिल भारत:		**8463.03***	**51.9**	**48.1**

* आंकड़ों को शून्यांत बनाया गया है।

विवरण-II

1991-92 के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं पर खर्च किए गए निवल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत (अनन्तिम)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर वास्तविक खर्च (1991-92)*	निवल राज्य घरेलू उत्पाद** (1991-92)	कालम (4) की तुलना में कालम (3) का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	329.62	37164.80	0.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.91	484.00	3.08
3.	असम	113.31	10429.80	1.09
4.	बिहार	506.50	25255.70	2.01
5.	गोवा	10.54	1143.80	0.92
6.	गुजरात	191.03	26358.70	0.72
7.	हरियाणा	72.16	14550.60	0.50
8.	हिमाचल प्रदेश	55.19	2797.90	1.97
9.	जम्मू व कश्मीर	67.32	3167.00	2.13
10.	कर्नाटक	209.44	26778.40	0.78
11.	केरल	136.90	13535.30	1.01
12.	मध्य प्रदेश	478.81	29357.30	1.63
13.	महाराष्ट्र	372.40	63847.60	0.58
14.	मणिपुर	15.73	760.50	2.07
15.	मेघालय	18.79	945.70	1.99
16.	मिजोरम	10.81	असूचित	—
17.	नागालैंड	15.24	680.50	2.24
18.	उडीसा	219.03	12214.90	1.79
19.	पंजाब	45.13	19878.80	0.23
20.	राजस्थान	295.19	19501.50	1.51
21.	सिक्किम	12.16	223.80	5.43
22.	तमिलनाडु	341.67	28868.20	1.18
23.	त्रिपुरा	15.90	असूचित	—
24.	उत्तर प्रदेश	750.18	56249.50	1.33
25.	पश्चिम बंगाल	290.86	36443.00	0.80

* प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण पेयजल सप्लाई, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एवं मरूभूमि विकास कार्यक्रम पर खर्च

** 2.6.1994 की वर्तमान कीमतों पर (अनन्तिम)

Recommendations of Hanumantha Rao Committee

3230. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Hanumantha Rao Committee for revamping the Drought-Prone Areas Programme-and the Desert Programme have submitted its recommendations to Government;

(b) if so. what are the details of recommendations made by the said Committee; and

(c) by when it is likely to be implemented in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) Details of the recommendations made by the Committee are given in the Annexure. *[See* Appendix 171, Annexure No. 52]